LOK SABHA

Friday March 3, 1978/Phalguna 12, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER: I have to inform the House of the sad demise of Shri Bashir Ahmad, a sitting Member of this House representing Fatehpur constituency of Uttar Pradesh. He passed away at Allahabad on the 2nd March, 1978 at the young age of 52.

Shri Bashir Ahmad was a very amiable and pleasing personality. An eminent lawyer and educationist he was author of a number of books and associated with a number of educational and social institutions. A forceful speaker, he used to take active interest in the proceedings of the House. In his untimely death the House has lost a promising parliamentarian.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may stand in silence for a short while as a mark of respect to the departed soul.

The Members then stood in silence for a short while.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश से हथकरघा कपड़े का निर्यात

*163. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश से हथकरघे के कितने और किन-किस किस्म के कपड़े का निर्यात किया गया ;

(ख) कितने मूल्य के कपड़े का (प्रति वर्ष) निर्यात किया गया ;

(ग) क्या निर्यात से हुए लाभ का कोई अंश हथकरघा के कपड़ा उत्पादकों को भी दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो (प्रति वर्ष) उन्हें लाभ का कितने प्रतिशत अंश दिया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) . विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). राज्यवार निर्यात आंकड़े संकलित नहीं किये जाते । अतः उत्तर प्रदेश से हथकरघा माल के निर्यात की मात्रा बताना सम्भव नहीं है । उत्तर प्रदेश से निर्यात किये जाने वाले सूती हथकरघा वस्त्रों तथा बने-बनाए वस्त्रों की मुख्य किस्में, बिछाने की चादरें, तकिये के गिलाफ, तौलिए, दरियां आदि हैं और रनिंग लैंथ वस्त्र भी हैं । हथकरघा

निर्यात संवर्धन परिषद के यहां पंजीयित उत्तर प्रदेश के निर्यातकों द्वारा पिछले दो वर्षों में निर्यात किये गये सूती हथकरघा वस्त्रों तथा बने-बनाए वस्त्रों का मूल्य निम्नलिखित था :

1975–76	1.38 करोड़ रु०
1976–77	2.38 करोड़ रु०

उत्तर प्रदेश के पंजीयित निर्यातकों के अलावा दिल्ली, बम्बई आदि की पार्टियां उत्तर प्रदेश से निर्यात योग्य किस्में हासिल करती हैं और अपने-अपने स्थल से माल निर्यात करती हैं। इस प्रकार के निर्यातों का मूल्य उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जब विनिर्माता व्यापारी निर्यातकों को माल बेचते हैं तो प्रायः उस सौदे में विनिर्माता के लिए लाभ का तत्व रहता है। किन्तु विनिर्माताओं द्वारा कमाये जा रहे लाभ की प्रतिशतता के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : जनता सरकार ने ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नई-नई योजनायें प्रारम्भ करने का वचन दिया है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि चूंकि उन के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से हथकरघा माल के निर्यात की मात्रा बताना सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग प्रमुख उद्योगों में से है। इसलिए इस की ओर विशेष ध्यान देने और इस को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश से 1975–76 में 1.38 करोड़ रुपये और 1976–77 में 2.38 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें कि उत्तर प्रदेश के हथकरघा उद्योग कुल कितना निर्यात हुआ है और कितना लाभ हुआ है।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैंने यह बताया है कि हर एक राज्य से कितना माल बाहर जाता है यह हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ लोग राज्य से बाहर भेजते हैं, कुछ बाहर के व्यापारी भी होते हैं चाहे बम्बई के हों या कलकत्ते के हों, वे भी वहां से ले कर भेजते हैं, इसलिए स्टेट-वाइज तो आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध हैं वह मैंने बताए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारी काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन को हम पूरा पूरा बढ़ावा दें और इसीलिए हम ने एक्सपोर्ट हाउसेज को ऐसा कहा है कि अगर छोटी इंडस्ट्रीज माल बाहर भेजती है तो उस के लिए हम जो सहूलियतें देते हैं उस में हम इस तरह गिनेंगे कि अगर एक लाख का माल उन्होंने भेजा तो उसे दो लाख का गिनेंगे स्माल स्केल और छोटी इण्डस्ट्रीज के लिए। हमारी तो पूरी नीति है कि छोटे उद्योगों और हथकरघा उद्योग के लिए हमारी पूरी-पूरी मदद रहे।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सचाई यह है कि छोटे उद्योग के जो हथकरघा बुनकर लोग है उन को उस लाभ का अंश बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। सही रूप में उन को उन के लेबर के बदले भी उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मिडिल मैन सारे का सारा मार्जिन ले रहा है। तो इस के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है कि उन को उन के लाभ का अधिक से अधिक अंश दिलवा सके ?

श्री मोहन धारिया : यह सही है कि जो मिडिल मैन होते हैं वे असली लाभ

उठाते हैं और जो छोटे छोटे हथकरघा बुनकर हैं उन्हें उचित रीति से मुनाफा नहीं देते हैं । उस के लिए उन की जितनी अधिक से अधिक कोआपरेटिव बनाएं या उन की खुद की एसोसिएशन बनाएं तो यह काम हो सकता है और इस के लिए हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं ।

श्री मनोहर लाल : जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स होता है, अधिकतर यह देखा गया है कि जो उस के मेम्बर होते हैं वही लोग उस का निर्यात करते हैं बजाय इस के कि बुनकर करें । इसलिए उन तक यह नहीं पहुंच पाता है । तो क्या माननीय मंत्री जो इस तरह की जांच करवाएंगे जिस से यह जो निर्यात होता है यह सही माने में बुनकर भाई ही करें बजाय इस के कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के मेम्बर करें और करप्शन फैलायें ?

श्री मोहन धारिया : उस में मैं जांच करूंगा ।

PROF. DALIP CHAKRAVARTY: Is the Minister aware that a larger percentage of the profit goes to the middleman? Is he aware that many of the handloom weavers in West Bengal and Assam are sitting idle for lack of yarn, dyes and just prices for the commodities they are producing. What steps Government is contemplating to remedy the situation?

SHRI MOHAN DHARIA: It is in this context that the Government has taken a very major decision that henceforth composite mills in big sector would not be allowed to produce whatever additional cloth is needed by the mills or even for export purposes. We shall encourage the decentralised sector. To make available the yearn and other inputs required for these small weavers, ever since I took charge—it is now with my colleague, Shri George Fernandes—we have adopted a scheme whereby the yarn is procured at the mill price from the spinning mills and is given to the apex societies of the States and they are distributing it. This is how several measures are being taken.

श्री रूपनाथ सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे बुनकरों का शोषण इस में होता है क्योंकि जो बिचौलिया होता है वह खरीद लेता है और उस से उन को उसका मुनाफ़ा नहीं होने पाता । इस के अलावा दूसरी कठिनाई यह होती है कि उन को सूत भी नहीं मिलता , रंग भी नहीं मिलता । जो बुनकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में बसते हैं जैसे प्रतापगढ़ , जौनपुर आदि के इलाके हैं और इलाहाबाद में मऊआइमा है, वहां के बुनकरों को सूत नहीं मिलता तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि बिलकुल सीधे जो बुनकर हैं उनको सूत उपलब्ध करा दिया जाय ?

श्री मोहन धारिया : जैसा मैंने अभी बताया कि उन को सूत और रंग उपलब्ध हो जाय उसी के लिए हम ने ऐसा किया है कि जो वहां की एपेक्स सोसाइटीज़ होती हैं या गवर्नमेंट के स्माल स्केल कारपोरेशन होते हैं .... उनसे हमने कहा हैं कि वे बटवारा करने का काम करें । दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि यू० पी० में बटवारे का काम जो था उसकी जिम्मेदारी वहां के कार्पोरेशन ने पहले ही नहीं ली थी लेकिन फिर कार्पोरेशन ने जिम्मेदारी ली है और मैं आशा करता हूं कि वहां भी अच्छी तरह से बटवारा हो जायेगा ।

श्री राम सेवक हजारी : अध्यक्ष महोदय, हथकरघा उद्योग हमारे देश में इतना विकसित था कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय भी निर्यात से काफी पैसा विदेशों से हमें मिलता था । मैं जानना चाहता हूं

इस उद्योग के विकास के लिए क्या सरकार कोई खास कदम उठा रही है जिससे इस उद्योग का सही विकास हो सके, बुनकरों को सही दिशा मिल सके और उनको अपनी मेहनत का सही दाम मिल सके ? क्या सरकार इस प्रकार के कदम उठाने जा रही है ?

श्री मोहन धारिया : इस विषय का सम्बन्ध तो उद्योग मंत्रालय से है फिर भी माननीय सदस्य की मालूमात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में 3.8 मिलियन (38 लाख) हथकरघे हैं जिन पर 1 करोड़ लोगों को एम्प्लाइमेंट मिला हुआ है लेकिन सभी को पूरा एम्पलाईमेंट नहीं मिलता। उनको कैसे एम्पलाईमेण्ट मिले, हथकरका उद्योग को कैसे पूरा प्रोटेक्शन मिले— इसके लिए काफी कदम उठाये गये हैं और हमें आशा है कि आने वाले कुछ दिनों में हथकरघा उद्योग के जो लोग हैं उनको अच्छी इनकम मिल सकेगी, अच्छा काम मिल सकेगा और यह इण्डस्ट्री आगे बढ़ सकेगी और इस प्रकार काफी लोगों की अन-एम्पलायमेण्ट प्राब्लम भी साल्व हो सकेगी।

Import of Articles in Short Supply

*166. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether in view of the comfortable foreign exchange reserves, Government have taken a decision to create buffer stocks by import of articles which are in short supply in the country and if so, the details thereof; and

(b) the action taken so far to arrange imports?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). The Government has decided to maintain buffer stocks of 12 million tonnes to foodgrains. A decision has also been taken to build up a buffer stock of fertilizers to the extent of 20 per cent of annual requirements. The canalising agencies, such as the State Trading Corporation and the Minerals and Metals Trading Corporation also try to ensure adequate stocks of sensitive articles such as edible oils and non-ferrous metals through imports so as to ensure their smooth suplies to demestic users. Government have been liberally releasing foreign exchange for import of articles of mass consumption which are in short supply in the country with a view to ensuring their adequate availability.

SHRI S. R. DAMANI: May I know what are the items of mass consumption which have been imported up to December, 1977 and the value thereof?

SHRI H. M. PATEL: I would not be able to give you the correct figures. But the items of mass consumption could not have been imported in any large quantity by individuals. Some of the mass consumption items are edible oils, non-ferrous metals and cotton. These items were certainly imported.

SHRI S. R. DAMANI: May I know whether the Government has drawn any plan to import the items of mass consumption and, if so, what are the items included for import in the next twelve months? Will the hon. Minister assure the House that the imports will be arranged in such a way that they will neither affect adversely the prices of the local produce or indigenous production nor the prices will shoot up on account of irregular imports? Secondly, I also want to know what efforts are being made to increase the indigenous production to meet the shortfall of the commodities of mass consumption in the country which we have to import.

MR. SPEAKER: It is almost a policy question.